उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 14 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(09/77)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला के नव निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने छात्र संघ पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन के पदाधिकारियों से महाविद्यालयों में अनुकूल शैक्षणिक माहौल एवं अनुशासन बनाये रखने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का अनुकूल शैक्षणिक माहौल छात्रों के बेहतर भविष्य के निर्माण में मददगार रहते है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की भी है। इसमें शिक्षकों व छात्रों के साथ ही छात्र संगठनो को भी सहयोग देना चाहिए। जीवन में कामयाबी के लिये अच्छी शिक्षा व तालीम जरूरी है।

इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष निशान्त मिश्रा, महासचिव पंकज कुमार, कोषाध्यक्ष निधि शर्मा, छात्रा प्रमुख सिमरन रावत के साथ ही बडी संख्या में छात्रगण उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(09/76)

राज्य के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सचिव सतर्कता विभाग श्री नितेश झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय जांच एजेंसियों (प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो) तथा राज्य की जांच एजेंसियो(सतर्कता अधिष्ठान, सीबीसीआईडी, अभिसूचना/सुरक्षा(एलआईयू) एवं एसटीएफ) के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श कर भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में परस्पर सूचना का आदान प्रदान करने हेतु प्रत्येक जांच एजेंसियों से नोडल अधिकारी नामित करने पर सहमति हुई।

इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव सतर्कता की अध्यक्षता में प्रत्येक माह विचार–विमर्श हेतु बैठक आयोजित किये जाने पर सहमति हुई।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(09/75)

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने बाल, महिला संरक्षण गृहों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे गृहों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाय। संरक्षण गृहों में सभी तरह की बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ पुस्तकालय, खेलकूद और मनोरंजन के साधन भी हों। तैनात सभी स्टाफ का पुलिस सत्यापन जरूर कराया जाय। सभी गृहों में विशेष आंगनवाड़ी केंद्र भी चलाए जाए। मुख्य सचिव शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में संचालित बाल/महिला संरक्षण गृहों के संचालकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि संरक्षण गृहों में सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं। नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग की जाय। संस्था में आने–जाने वाले सभी आगंतुकों का विवरण आगंतुक पंजिका में दर्ज किया जाय। 10 वर्ष तक के बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं की संस्था में शत् प्रतिशत महिला कार्मिक ही तैनात किए जाए। इसके साथ ही संस्थाओं में बाल समिति और प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाय।

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय नारी निकेतन, जिला शरणालय एवं संरक्षण गृह संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार स्वाधार गृह, उज्ज्वला गृह का संचालन करती है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। बताया गया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा राज्य में संचालित 42 संस्थाओं का सोशल ऑडिट कराया गया। बैठक में ऑडिट की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। कतिपय सुविधाओं और व्यवस्थाओं को छोड़कर ऑडिट में कोई गंभीर कमी नहीं पाई गई है। उन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर सचिव महिला कल्याण श्री राम विलास यादव, निदेशक महिला कल्याण श्री योगेंद्र यादव सहित आई.सी.डी.एस. के अनेक अधिकारी और संस्था संचालक उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(09/74)**

वाप्कोस लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड में 21 घाटों का निर्माण दिसम्बर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 15 लघु पन बिजली परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। रिस्पना और बिन्दाल नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो की डीपीआर अन्तिम चरण में है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में वाप्कोस लिमिटेड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम) के अधिकारियों ने भेंट के दौरान जानकारी दी कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत–नेपाल सीमा पर बनने वाली बहुउद्येशीय विद्युत परियोजना पंचेश्वर बांध की डीपीआर तैयार कर ली गई है। फोरेस्ट व इन्वायरमेन्टल क्लियरेन्स के अन्य कार्य प्रगति पर है। परियोजना के प्रति स्थानीय लोगो में उत्साह है। क्षेत्र वासियों को विश्वास है कि विस्थापन सुखद होगा। परियोजना का लाभ बिजली उत्पादन व एक बड़े क्षेत्र की सिचाई के अतिरिक्त ऊधमसिंह नगर जिले में ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति के लिए भी होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वाप्कोस लिमिटेड को उत्तराखण्ड सरकार की ओर से हर संभव सहयोग व सहायता का आश्वासन दिया।

बैठक में वाप्कोस लिमिटेड के श्री अनुपम मिश्र व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।